

पत्रसूचनाकार्यालय (रक्षाविंग)
भारतसरकार

‘हरकामदेशकेनाम’

नईदिल्ली:श्रावण14, 1944
शुक्रवार: 05अगस्त 2022

तेजसलड़ाकूविमान

रक्षामंत्रालय (एमओडी) के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के एकरक्षा उपक्रम, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), ने एलसीएवर्ग के विमानों के लिए एरॉयल मलेशियन एयरफोर्स (आरएमएएफ), मलेशिया से फरवरी, 2019 में प्राप्त सूचनार्थ अनुरोध (आरएफआई) का उत्तर दिया था।

उसके बाद, एचएएल ने अक्टूबर, 2021 में 18 फाइटर लीड इन ट्रेनर-लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एफएलआईटी-एलसीए) के लिए आरएमएएफ, मलेशिया द्वारा जारी निविदा के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) का उत्तर दिया था और एचएएल ने एलसीए तेजस दो सीटों वाले वैरिएंट की पेशकश की थी। एलसीए विमान में रुचि दिखाने वाले अन्य देश: अर्जेंटीना; आस्ट्रेलिया; मिस्र; यू.एस.ए.; इंडोनेशिया और फिलिपींस हैं।

सरकार ने देश में रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए विगत कुछ वर्षों में कई पहलों की हैं और सुधार किए हैं, जिससे इनके उत्पादन में विस्तार हुआ है। इन पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: -

- (1) रक्षा अर्जन प्रक्रिया (डीएपी) -2020 के अंतर्गत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत मदों की अधिप्राप्तिको प्राथमिकता देना।
- (2) उद्योग द्वारा संचालित डिजाइन एवं विकास के लिए मार्च, 2022 में 18 प्रमुख रक्षा प्लेटफार्मों की घोषणा।
- (3) सेनाओं की कुल 310 मदों की तीन 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों' और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) की कुल 2958

मदोंकीदो ' सकारात्मस्वदेशीकरणसूचियों ' ,

कीअधिसूचना ,

जिसकेलिएउनकेसामनेदर्शायीगईसमय-सीमाकेबादइनमदोंकेआयातपरप्रतिबंधहोगा।

- (4) लंबीवैधताअवधिकेसाथऔद्योगिकलाइसेंसिंगप्रक्रियाकासरलीकरण।
- (5) स्वचालितमार्गकेअंतर्गत⁷⁴
प्रतिशततकएफडीआईकीअनुमतिदेकरप्रत्यक्षविदेशीनिवेश (एफडीआई) नीतिकाउदारीकरण।
- (6) मेकप्रक्रियाकासरलीकरण।
- (7) स्टार्टअप्सएवंसूक्ष्मलघुएवंमध्यमउद्यमों (एमएसएमई)
कोशामिलकरकेरक्षाउत्कृष्टताहेतुनवाचार (आईडेक्स) योजनाकीशुरूआत।
- (8) सार्वजनिकअधिप्राप्ति (मेकइनइंडियाकोवरीयता) आदेश-2017 काकार्यान्वयन।
- (9) एमएसएमईसहितभारतीयउद्योगद्वारास्वदेशीकरणकीसुगमताकेलिएसृजननामकएकस्वदेशीपोर्टलकीशुरूआत।
- (10) उच्चगुणकोंकीसुविधाकेसाथरक्षाविनिर्माणकेलिएनिवेशएवंप्रौद्योगिकीहस्तांतरणआकर्षितकरनेपरबलदेतेहुएऑफसेटनीतिमेंसुधार।
- (11) दोरक्षाऔद्योगिकगलियारों, उत्तरप्रदेशऔरतमिलनाडुमेंएक-एक, कीस्थापना।
- (12) देशमेंरक्षाप्रौद्योगिकीकेविकासकोबढ़ावादेनेकेलिएचिन्हित²⁵
प्रतिशतरक्षाआरएंडडीबजटकेसाथउद्योग,
स्टार्टअप्सएवंशैक्षिकसंस्थाओंकेलिएरक्षाअनुसंधानएवंविकास (आरएंडडी) खोलना; और
- (13) घरेलूस्रोतोंसेअधिप्राप्तिकेलिएसेनाकेआधुनिकीकरणकेलिएरक्षाबजटकेआवंटनमेंप्रगामीवृद्धि,
इत्यादि।

रक्षाराज्यमंत्रीश्रीअजयभट्टनेआजलोकसभामेंश्रीमतीकीनओझाएवंअन्यद्वारापूछेगएएकप्रश्नकेलिखित उत्तरमेंयहजानकारीलोकसभाकेपटलपररखी।

एबीबी/डीके/डीएस

पत्रसूचनाकार्यालय (रक्षाविंग)
भारतसरकार

'हरकामदेशकेनाम'

नईदिल्ली:श्रावण14, 1944
शुक्रवार: 05 अगस्त 2022

वेतनोंपरहोनेवालाव्यय

01अप्रैल 2022 कीस्थितिकेअनुसार, रक्षासेनाओंमेंपेंशनभोगियोंकीकुलसंख्या35,21,876 है।वर्ष2012 से2022 तकपेंशनभुगतानकेवास्तविकअनुमानइसप्रकारहैं:-

(राशिकरोड़में)

वर्ष	रक्षापेंशन (वास्तविकव्यय)
2012-13	43,367.71
2013-14	45,499.54
2014-15	60,449.75
2015-16	60,237.60
2016-17	87,825.80
2017-18	91,999.58
2018-19	1,01,774.61
2019-20	1,17,810.24
2020-21	1,28,065.77
2021-22	1,16,799.85

प्रतिष्ठानव्ययमेंवेतन, चिकित्साखर्च, मजदूरी, समयोपरिभत्ता, विदेशयात्रासंबंधीखर्च, घरेलूयात्रासंबंधीखर्च, कार्यालयखर्च, सामग्रियांएवंआपूर्तियां, प्रकाशन, विज्ञापनएवंप्रचार, प्रशिक्षण, अन्यप्रशासनिकखर्च, पीओएल, राशनलागत, वस्त्रएवंशिविर, पेशेवरसेवाएं, किरायादरएवंकर, रॉयल्टी, पेंशनसंबंधीभुगतान, पुरस्कारएवंलघुकार्य, मोटरवाहन, सूचनाप्रौद्योगिकीइत्यादिजैसेप्रतिष्ठानसेसंबंधितसभीव्ययशामिलहोतेहैं।प्रतिष्ठानव्ययमेंवेतनएवंअवेतनदोनोंखंडशामिलहोतेहैं।विगतपांचवर्षोंकेदौरानरक्षाकार्मिकोंकेवेतन, अवेतन (रक्षाभंडारअधिप्राप्तिसहित) औरपेंशनपरकिएगएकुलव्ययकाब्यौराइसप्रकारहै:-

(करोड़रु. में)

वर्ष	वेतनपरकुलव्यय	अवेतनपरकुलव्यय	रक्षापेंशनपरकुलव्यय
2017-18	1,34,354.90	47,766.54	91,999.58
2018-19	1,41,508.00	50,951.59	1,01,774.61
2019-20	1,47,972.55	59,599.60	1,17,810.24
2020-21	1,45,884.74	59,855.17	1,28,065.77
2021-22*	1,57,893.39	70,668.90	1,16,799.85

*अनंतिमआंकड़ें

वर्ष 2014-15 से 2022-23 तकबजटअनुमानों (बीई) मेंरक्षामंत्रालय (सभीचारअनुदान) कोप्रदानकिएगएबजटकाब्यौरानीचेसारणीमेंदियागयाहै :

(करोड़रु. में)

वित्तीयवर्ष	बीईआवंटन
2014-15	2,85,202.87
2015-16	3,10,079.60
2016-17	3,40,921.98
2017-18	3,59,854.12
2018-19	4,04,364.71
2019-20	4,31,010.79
2020-21	4,71,378.00
2021-22	4,78,195.62
2022-23	5,25,166.15

उपर्युक्तसारणीसेअनुमानलगायाजासकताहैकिरक्षाकेलिएबजटआवंटनमेंनिरंतरवृद्धिहुईहै।

मंत्रालयमेंअन्यदेशोंकेव्ययसंबंधीआंकड़ेंनहींरखेजातेहैं।तथापि,
स्टॉकहोमअंतर्राष्ट्रीयशांतिअनुसंधानसंस्थान
कीवेबसाइटपरउपलब्धआंकड़ोंकेआधारपरवर्ष
केलिएशीर्षपांचदेशोंकेव्ययसंबंधीआंकड़ेइसप्रकारहैं : -

(एसआईपीआरआई)

2021

(मौजूदामिलियनअमरीकीडालरमें)

क्रमसं.	देश	वर्ष 2021 केलिएव्यय
1	संयुक्तराज्यअमेरिका	800,672.20
2	चीन	293,351.90
3	भारत	76,598.00
4	युनाइटेडकिंगडम	68,336.40
5	रूस	65,907.70

उपर्युक्तसारणीसेदेखाजासकताहैकिभारतकारक्षाव्ययवर्ष
मेंरक्षाव्ययकरनेवालेप्रमुखदेशोंमेंतीसरेस्थानपरहै।यहउल्लेखकरनाप्रासंगितहोगाकिसरकारीसंसाधनएक
निश्चितलागतसेप्राप्तहोतेहैंऔरतदनुसार,

2021

सरकारकेसमग्रसंसाधनसमूहकेआधारपरविभिन्नप्रतिस्पर्धीप्राथमिकताओंकेबीचआवंटनकिएजातेहैं।यहभीउल्लेखनीयहैकिकेन्द्रीयमंत्रालयोंमेंरक्षामंत्रालयकाबजटसर्वाधिकहै।

पूँजीगतव्ययमेंवृद्धिकरनेकेलिएचलरहेरक्षासुधारोंकेभागकेरूपमेंपूँजीअर्जनकीपरियोजनाओंकोनियंत्रितकरनेवालेप्रक्रियागतदिशा-निर्देशोंमेंसंशोधनकियागयाहैऔररक्षाअर्जनप्रक्रिया, 2020 केतहतअधिसूचितकियागयाहै।इसकेअलावा, सेनामुख्यालयोंऔरफील्डकमानोंमेंपीएसओकेओवरहाल, रिफिटएवंउन्नयनकेलिएवित्तीयशक्तियोंकेनएप्रत्यायोजनसहितमुख्यालयस्तरपरसंवर्धितप्रत्यायोजितपूँजीगतअधिप्राप्तिशक्तियोंकेसाथसेनाओंकोअधिकारदिएगएहैं।

रक्षाराज्यमंत्रीश्रीअजयभट्टनेआजलोकसभामेंश्रीदीपकअधिकारी (देव) एवंअन्यद्वारापूछेगएएकप्रश्नकेलिखितउत्तरमेंयहजानकारीलोकसभाकेपटलपररखी।

एबीबी/डीके/डीएस

पत्रसूचनाकार्यालय (रक्षाविंग)
भारतसरकार

'हरकामदेशकेनाम'

नईदिल्ली:श्रावण14, 1944
शुक्रवार: 05 अगस्त 2022

रक्षाविनिर्माणमेंअनुसंधानऔरविकास

रक्षाविनिर्माणमेंअनुसंधानऔरविकासकोबढ़ावादेनेकेलिएसरकारद्वाराकिएगएउपायनिम्नानुसारहैं

:-

- डीआरडीओनेडीआरडीओद्वाराविकसितप्रणालियोंकेलिएविकास-सह-
(डीसीपीपी) उत्पादनसाझेदार
उद्योगोंकीभागीदारीकोसुनिश्चितकरतीहैकेचयनकेलिएएकनीतिप्रस्तुतकीहैजोविकासचक्रकेआरंभसे
सीमामेंकमीलातीहै।- औरविकाससेप्रवेशचक्रकीसमय
- डीआरडीओनेअपनेउद्योगसाझेदारों (डीसीपी) विकाससहउत्पादनसाझेदार) /उत्पादनएजेंसी
(पीए)
केलिए 'शून्य' टीओटीशुल्कऔरभारतीयसशस्त्रसेनाओंतथासरकारीविभागकोआपूर्तिकेलिए 'शून्य'
रॉयल्टीकेसाथनईटीओटीनीतिऔरप्रक्रियाकोप्रख्यापितकियाहै।यहवैश्विकबाजारमेंभारतीयउद्योगों
कीक्षमताओंऔरप्रतिस्पर्धात्मकतामेंवृद्धिकरेगी।यहउच्चतरआत्मनिर्भरताकीप्राप्तिकेलिएरक्षाविनिर्मा
णक्षेत्रमेंभारतीयउद्योगोंकोऔरअधिकप्रोत्साहनभीप्रदानकरेगी।
- डीआरडीओनेभारतीयउद्योगोंकोडीआरडीओपेटेंटकाउपयोगकरनेकेलिएनिःशुल्कपहुंचकोसुगमब
नानेहेतुनईपेटेंटनीतिकोप्रख्यापितकियाहै।यहभारतीयउद्योगोंकाउनकेअनुसंधानएवंविकासकोऔर
अधिकप्रोत्साहनदेनेतथानईप्रौद्योगिकीयोंकेविकासकेलिएडीआरडीओद्वाराकिएगएनवाचारोंतकपहुं
चप्रदानकरेगी।
- डीआरडीओनेप्रौद्योगिकीविकासनिधि (टीडीएफ)
कियाहैजोवोन्मेषीरक्षाउत्पादोंकेडिजाइनएवंविकासकेलिएभारतीयउद्योगोंसहितएमएसकाशुभारंभ
-एमईएवंस्टार्ट
अप्सकेलिएवित्तीयसहायताप्रदानकरतीहै।यहसहायताअनुदानकेमाध्यमसेसशस्त्रसेनाओंद्वाराप्रयुक्त
प्रणालियों,
घटकोंऔरशस्त्रोंकेलिएप्रौद्योगिकीयोंकेडिजाइनएवंविकासहेतुवित्तपोषणउपलब्धकरतीहै।टीडीएफ
नवाचारकोप्रोत्साहनदेनेऔरस्वदेशीरक्षाविनिर्माणपारितंत्रकेविकासकोबढ़ावादेनेहेतुएकसमर्थकारी
पारितंत्रकानिर्माणकरनेमेंयोगदानदेतीहै।

विगततीनवर्षोंकेदौरानडीआरडीओमेंविभिन्नअनुसंधानएवंविकासपरियोजनाओंकेतहतपरियोजनाओंऔरउपयोगकेलिएस्वीकृतधनराशिकाविवरणनिम्नानुसारहै:

वर्ष	स्वीकृतपरियोजनाओंकीसंख्या	धनराशि
2019	81	4895.86 करोड़रुपए
2020	88	4031.7 करोड़रुपए
2021	74	19978.90 करोड़रुपए
जनवरी सेआजकीतिथितक	2022 39	9078.91 करोड़रुपए
कुल	282	37,985.37 करोड़रुपए

सरकारनेविगतकुछवर्षोंमेंअनेकनीतिगतपहलेंकीहैऔररक्षाउपस्करकेस्वदेशीडिजाइन, विकासऔरविनिर्माणकोप्रोत्साहितकरनेकेलिएसुधारकेएहैंजिससेदेशमेंरक्षाविनिर्माणएवंप्रौद्योगिकीमेंआत्मनिर्भरताकोबढ़ावामिलसकेकुछमहत्वपूर्णउपायनिम्नानुसारहैं:-

- रक्षाअर्जनप्रक्रिया (डीएपी) - 2020
केतहतघरेलूस्रोतोंसेपूँजीगतमदोंकीअधिप्राप्तिकोप्राथमिकतादेना।मार्च, 2022
मेंउद्योगद्वारासंचालितडिजाइनएवंविकासकेलिए 18 प्रमुखरक्षाप्लेटफार्मोंकीघोषणा।
- सेनाओंकीकुल 310 मदोंकीतीन 'सकारात्मकस्वदेशीकरणसूचियों'
औरसार्वजनिकक्षेत्रकेरक्षाउपक्रमों (डीपीएसयू) कीकुल 2958 मदोंकीदो
'सकारात्मकस्वदेशीकरणसूचियों' कीअधिसूचनाजिनकेलिएउनकेसामनेनिर्दिष्टसमय-
सीमाओंकेबादआयातपरप्रतिबंधहोगा।
- लम्बीवैधताअवधिकेसाथऔद्योगिकलाइसेंसप्रदानकरनेकीप्रक्रियाकासरलीकरण।
- स्वचालितमार्गकेतहत 74 प्रतिशतएफडीआईकीअनुमतिदेकरप्रत्यक्षविदेशीनिवेश
(एफडीआई) काउदारीकरण।
- मेकप्रक्रियाकासरलीकरण, स्टार्टअपसूक्ष्म, लघुऔरमध्यमउद्यमों (एमएसएमई)
कोशामिलकरकेरक्षाउत्कृष्टतायोजना (आईडेक्स) काशुभारंभ।
- लोकअधिप्राप्ति (मेकइनइंडियाकोवरीयता) आदेश, 2017 काकार्यान्वयन।
- एमएसएमईसहितभारतीयउद्योगद्वारास्वदेशीकरणकोसरलऔरसहजबनानेकेलिए 'सृजन'
नामकएकस्वदेशीकरणपोर्टलकाशुभारंभ।
- उच्चतरगुणकोंकेआवंटनद्वारा रक्षाविनिर्माणकेलिएनिवेशकोआकर्षितकरनेऔरप्रौद्योगिकीहस्तांतरण
कोप्रोत्साहनदेनेकेसाथऑफसेटनीतिमेंसुधार।
- दोरक्षाऔद्योगिकगलियारोंउत्तरप्रदेशऔरतमिलनाडुप्रत्येकमेंसेएक -एक, कीस्थापना।
- 25 प्रतिशतरक्षाअनुसंधानएवंविकासबजटकेसाथउद्योग,
स्टार्टअपऔरशैक्षणिकसंस्थानोंकेलिएरक्षाअनुसंधानएवंविकास (आरएंडडी) शुरूकरना।
- घरेलूस्रोतोंसेअधिप्राप्तिकेलिएसैन्यआधुनिकीकरणकेरक्षाबजटकेआवंटनमेंप्रगामीवृद्धिआदि।

रक्षाराज्यमंत्रीश्रीअजयभट्टनेआजलोकसभामेंश्रीपीवीमिधुनरेड्डीऔरडॉसंजीवकुमारशिंंगरीद्वारापूछेगए
एकप्रश्नकेलिखितउत्तरमेंयहजानकारीलोकसभाकेपटलपररखी।

एबीबी/डीके/डीएस

पत्रसूचनाकार्यालय (रक्षाविंग)
भारतसरकार

‘हरकामदेशकेनाम’

नईदिल्ली:श्रावण14, 1944
शुक्रवार: 05 अगस्त 2022

पूर्वसैनिकोंकाकल्याण

देशमेंभूतपूर्वसैनिकों (ईएसएम) कीसंख्याअनुबंध-कपरदीगईहै।

केंद्रीयसैनिकबोर्डपूरेदेशमेंपूर्वसैनिकोंऔरउनकेआश्रितोंकेकल्याणऔरपुनर्वासहेतुयोजनाओंकाकार्यान्वयनकरताहै।इसकाब्यौराअनुबंध-खपरदियागयाहै।पुनर्वासमहानिदेशालय (डीजीआर) विभिन्नपुनर्वासयोजनाओंकोकार्यान्वितकरताहै।ब्यौराअनुबंध-गपरदियागयाहै।

(क) पिछलेकुछवर्षोंमेंनिम्नलिखितयोजनाओंकीलाभराशिमेंवृद्धिकीगईहै।ब्यौरानिम्नानुसारहै:-

(i) दिनांक 01 अप्रैल 2016 सेविवाहअनुदानकोप्रतिपुत्री 16000/-रु. रुपएसेबढ़ाकर 50000/-रु. करदियागयाहै।

(ii) दिनांक 01 अप्रैल 2017 सेपेन्युरीअनुदानको 1000/- रुपएसेबढ़ाकर 4000/-रु. प्रतिमाहकरदियागयाहै।

(iii) दिनांक 01 अगस्त 2021 से 100% दिव्यांगबालअनुदानको 1000/-रु. सेबढ़ाकर 3000/-रु. प्रतिमाहकरदियागयाहै।

(iv) दिनांक 01 अप्रैल 2022 सेदिव्यांगपूर्वसैनिकोंहेतुमोबिलिटीउपकरणराशि 57000/-रु. सेबढ़ाकर 1,00,000/-रु. करदीगयीहै।

(v) दिनांक 01 अप्रैल2022 सेपूर्वसैनिकोंकेबच्चोंकोप्रदानकियाजानेवालाअनाथअनुदान 1000/-रु. प्रतिमाहसेबढ़ाकर 3000/-रु. करदियागयाहै।

(ख) पेन्युरी, विवाहऔरशिक्षाअनुदानोंकेपिछलेमामलोंकेनिपटानकेलिएवित्तीयवर्ष 2021-22 केदौरानअतिरिक्त 320करोड़रुपएभीआबंटितकिएगएथे।

। पूर्वसैनिकोंसैनिकोंकाकल्याण। केबारेमेंउल्लिखितअनुबंध-क

राज्य/संघशासितक्षेत्र : 31 दिसम्बर, राज्य/संघशासितक्षेत्र 31 दिसंबर 2021
तक पूर्वसैनिकोंकी संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघशासितक्षेत्र	पूर्वसैनिकोंकी संख्या
1.	आंध्रप्रदेश	72706
2.	अरुणाचलप्रदेश	623
3.	असम	38761
4.	बिहार	114383
5.	छत्तीसगढ़	7202
6.	गोवा	2487
7.	गुजरात	31573
8.	हरियाणा	164773
9.	हिमाचलप्रदेश	123210
10.	झारखंड	28070
11.	कर्नाटक	89727
12.	केरल	179724
13.	मध्यप्रदेश	54203
14.	महाराष्ट्र	193503
15.	मणिपुर	7627
16.	मेघालय	2843
17.	मिजोरम	5955
18.	नागालैंड	2940
19.	ओडिशा	43335
20.	पंजाब	339367
21.	राजस्थान	201434
22.	सिक्किम	1121
23.	तमिलनाडू	127932
24.	तेलंगाना	36721
25.	त्रिपुरा	2279
26.	उत्तरप्रदेश	391040
27.	उत्तराखंड	135778
28.	पश्चिमबंगाल	95003
29.	अंडमान एवं निकोबार (यूटी)	667
30.	चंडीगढ़ (यूटी)	9991
31.	दादरानगरहवेली (यूटी)	0
32.	दिल्ली (यूटी)	61496
33.	जम्मू तथा कश्मीर (यूटी)	71702
34.	लक्षद्वीप (यूटी)	0

35.	लेहतथालद्वाख	5364
36.	पुदुचेरी (यूटी)	1792
	कुल (भारत)	2645332

॥ पूर्वसैनिकोंकाकल्याण ॥ केबारेमेंउल्लिखितअनुबंध-ख

केंद्रीयसैनिकबोर्ड (केएसबी) द्वारापूर्वसैनिकों/विधवाओंऔरवीरगति प्राप्त सैनिकों कीविधवाओंऔरउनकेआश्रितोंकोप्रदानकीजानेवालीविभिन्नकल्याणकारीयोजनाओंकाविवरण

1. आरएमईडब्ल्यूएफकेतहतसशस्त्रबलइंजादिवसनिधिमेंसेदिएजानेवालेलाभ:-

क्र.सं.	अनुदान	राशि (रुपएमें)
(क)	पेन्युरीअनुदान (65 वर्षऔरउसकेऊपर) (हवलदाररैंकतककेगैर-पेंशनर)	4,000/-रु. प्रतिमाह (आजीवन) 01 अप्रैल 17 सेप्रभावी
(ख)	शिक्षाअनुदान (दोबच्चोंतक) (i) लड़का/लड़कीकोस्नातकतक (ii) परास्नातकतकविधवाओंहेतु (हवलदाररैंकतककेपेंशनर/गैर-पेंशनर) औरदोबच्चोंतक	1,000/-रु. प्रतिमाह
(ग)	दिव्यांगबालअनुदान (जेसीओरैंकतककेपेंशनर/गैर-पेंशनर)	3,000/-रु. प्रतिमाह
(घ)	पुत्रीकेविवाहहेतुअनुदान (02 पुत्रियोंतक) (हवलदाररैंकतककेपेंशनर/गैर-पेंशनर) विधवापुनर्विवाहअनुदान (हवलदाररैंकतककेपेंशनर/गैर-पेंशनर) *यदिकेवलदिनांक 21 अप्रैल 16 कोयाउसकेबादहीविवाहित	50,000/-रु.*
(ङ)	चिकित्साउपचारअनुदान (हवलदाररैंकतककेपेंशनर/गैर-पेंशनर)	30,000/-रु. (अधिकतम)
(च)	अनाथअनुदान (सभीरैंकोंकेपेंशनर/गैर-पेंशनर) • पूर्वसैनिकोंकीपुत्रियोंकोविवाहहोनेतक। • पूर्वसैनिकोंकेएकपुत्रको 21वर्षकीआयुतक।	3,000/-रु. प्रतिमाह (01 अप्रैल 2022 सेप्रभावी)
(छ)	विधवाओंहेतुव्यावसायिकप्रशिक्षणअनुदान (हवलदाररैंकतककेपेंशनर/गैर-पेंशनर)	20,000/-रु. (एकबारगी)

2. **सभीरैंकोंकेगैर-पेंशनभोगीपूर्वसैनिकों कोएएफएफडीकोषसेगंभीररोगअनुदान :-**

(क)	निम्नानुसारसूचीबद्धकिएगएगंभीररोग :- एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, सीएबीजी, ओपनहार्टसर्जरी, वाल्वरिप्लेसमेंट, पेसमेकरइंप्लांट, रीनलइंप्लांट, प्रोस्टेटसर्जरी, ज्वाइंटरिप्लेसमेंटऔरसेरेब्रलस्ट्रोक अन्यरोग: जहांउपचारपर 1.00 लाखरुपएसेअधिकखर्चकिएगएहों।	अधिकारियोंऔरपीबीओआरकेलिएकुलव्ययकाक्रमशः 75%/90% । 1.25 लाखरुपएतक (अधिकतम)
(ख)	डायलिसिसऔरकैंसरउपचार	अधिकारियोंऔरपीबीओआरकेलिएकुलव्ययकाक्रमशः 75%/90% । प्रत्येकवित्तीयवर्षमेंअधिकतमकेवल 75,000/-रु. तक

3. **संशोधितस्कूटरअनुदान** - एकलाखरुपएउनपूर्वसैनिकोंकोप्रदानकिएगए,
जोसेवाकेपश्चात्50% याअधिककीदिव्यांगताकेसाथदिव्यांगश्रेणीमेंआतेहैंऔरजोएकीकृतमुख्यालय (सेना,
नौसेनाऔरवायुसेना) कीएजीशाखाकीयोजनाकेतहतकवरनहींहोतेहैं।

4. **आवासऋणपरसहायताराशि** - युद्धदिवंगत,
युद्धदिव्यांगोंऔरशांतिकालकेदौरानहताहतोंकोगृहनिर्माणकेलिएबैंकों/सार्वजनिकक्षेत्रसंस्थानोंसेलिएगएआ
वासऋणपरसहायताराशिप्रदानकरतेहुए50%ब्याजकापुनर्भुगतानकेंद्रीयसैनिकबोर्डद्वाराकियाजाताहै।
1,00,000/- रुपए (अधिकतम) ।

5. **प्रधानमंत्रीछात्रवृत्तियोजना** -
पाठ्यक्रमोंकीसंपूर्णअवधिकेदौरानपात्रबच्चोंकोमेरिटपरआधारितकुल 5500
छात्रवृत्तियांप्रदानकीजातीहैं।छात्रवृत्तिकीदरेंनिम्नानुसारहैं :-

- (क) लड़कोंकेलिए 2500/-रु. प्रतिमाह।
- (ख) लड़कियोंकेलिए 3000/-रु. प्रतिमाह।

6. **भूतपूर्वसैनिकोंकेपुनर्वासमेंसम्मिलितसंस्थानोंकोवित्तीयसहायता :-**

क्र.सं	संगठन	सहायता/अनुदानकीमात्रा
.		

(क)	पैराप्लेजिकपुनर्वासकेंद्र (i) किरकी (ii) मोहाली	स्थापनाअनुदान (प्रतिवर्ष) (i) 1.20 करोड़रुपए (अप्रैल 16 सेप्रभावी) (ii) 10,00,000 /-रु. (अप्रैल 15 सेप्रभावी)	30,000 /-रु. प्रतिवर्ष प्रतिनिवा सी
(ख)	अखिलभारतीयगोरखाभूतपूर्वसैनिककल्याणसंगठन, देहरादून	12,00,000/-रु.	प्रतिवर्ष
(ग)	चेशरहोम्स (i) लखनऊ, दिल्लीऔरदेहरादून	15,000/-रु.	प्रतिवर्षप्रतिनिवासी
(घ)	युद्धस्मारकहॉस्टल 36 युद्धस्मारकहॉस्टलहैंजोकिशहीदोंकीविधवाओं/युद्धदिव्यां गोंकेबच्चों, संबद्धऔरगैरसंबद्धमामलोंमेंआश्रयप्रदानकरतेहैं।	1350/-रु.	प्रतिमाह

7.

**भारतसरकारकेनामितिकेतौरपररक्षाकार्मिकोंकेबच्चोंहेतुचिकित्सा/दंतचिकित्साकालेजोंमें
सीटोंकाआरक्षण :-**

स्वास्थ्यपरिवारकल्याणमंत्रालयकेद्वाराकेंद्रीयसैनिकबोर्डकोभारतसरकारकेनामितिकेतौरपररक्षाकार्मिकोंके
बच्चोंकेलिएकुल 37 एमबीबीएससीटेंऔरबीडीएसपाठ्यक्रमकी 3 सीटेंआबंटितकीगईहैं।

॥ पूर्वसैनिकोंकाकल्याण ॥ केबारेमेंउल्लिखितअनुबंध-ग

पुनर्वासमहानिदेशालय (डीजीआर) केद्वारानिम्लिखितकेमाध्यमसेपूर्वसैनिकों
केपुनर्वासकेलक्ष्यकोप्राप्तकियाजानाअपेक्षितहै :-

(क)

नएकामकाज/कार्योंकोकरनेकेलिएतैयारकरनेहेतुआवश्यकप्रशिक्षणप्रदानकरकेपूर्वसैनि
कोंकेकौशलकाउन्नयनकरनाऔरपुनःनियोजनकोतलाशनेमेंभूतपूर्वसैनिकोंकीसहायताकरना।

(ख) सरकारी/अर्ध-

सरकारी/सार्वजनिकक्षेत्रकेसंगठनोंमेंरोजगारअवसरप्रदानकरनेकेलिएनिरंतरप्रयासकरना।

(ग) कारपोरेटक्षेत्रमेंपूर्वसैनिकोंकेपुनःनियोजनकीसुविधाकेलिएसक्रियकार्रवाईकरना।

(घ) स्वरोजगारकेलिएनिम्लिखितयोजनाओंकेमाध्यमसेनौकरियांप्रदानकरना :-

- (i) पूर्वसैनिक (ईएसएम) कोयलालदान और परिवहन योजना
- (ii) विधवाओं और दिव्यांग पूर्वसैनिकों के लिए कोयला टिप्पर अटैचमेंट योजना
- (iii) सुरक्षा एजेंसी योजना
- (iv) तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए योजना
- (v) 8% कोटा योजना के तहत तेल उत्पाद एजेंसियों के आबंटन हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करना
- (vi) कंपनी स्वामित्व वाले कंपनी संचालित (कोको) बिक्री केंद्र प्रबंधन
- (vii) मदर डेयरी केमिक्ल बूथ और फल व सब्जी (सफल) दुकानों का आबंटन
- (viii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पूर्वसैनिकों (अधिकारियों) के द्वारा सीएनजी स्टेशन का प्रबंधन
- (ix) नियमित एलपीजी वितरण अधिकार का आबंटन करने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करना
- (x) खुदरा बिक्री केंद्र (पेट्रोल और डीज़ल) के आबंटन के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करना।

रक्षारज्यमंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोकसभामें श्री रामचरण बोहरा और श्री सुनील कुमार मंडल द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी लोकसभा के पटल पर रखी।

एबीबी/डीके/डीएस

/लोकसभा/

“33”
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्रसूचना कार्यालय (रक्षाविंग)

भारत सरकार

‘हरकामदेशकेनाम’

नई दिल्ली: श्रावण 14, 1944

शुक्रवार: 05 अगस्त 2022

रक्षा अनुसंधान संस्थान

आज की तारीख तक देश में डी आर डी ओके पांच युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं सहित प्रयोगशालाएं/स्थापनाएं हैं।

46

रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

- युवाओं को नवीनतर नवाचारों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पांच युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं (डीवाईएसएल) का सृजन- युवा वैज्ञानिकों/अभियंताओं को डी आर डी ओके से जुड़ने के लिए आकर्षित करने हेतु तथा उभरते हुए इंजीनियरिंग क्षेत्रों एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकी, कॉग्निटिव प्रौद्योगिकी, असिमिटिक प्रौद्योगिकी तथा स्मार्ट मेटैरियल में आर एण्ड डी वातावरण प्रदान करने और युवा वैज्ञानिकों को अपनी प्रतिभा साबित करने की पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए डी आर डी ओके पांच युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं (डीवाईएसएल) का सृजन किया है।
- डी आर डी ओके ने मेधावी, युवा वैज्ञानिकों/अभियंताओं को उच्चतर योग्यता अर्जित करने अथवा अनुसंधान अनुभव की प्राप्ति के लिए अनुसंधान कार्य करने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए अनुसंधान छात्रवृत्तियों की योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त, डी आर डी ओके द्वारा अन्य योजनाएं जैसे आईपी आर द्वारा सहायता अनुदान स्कीम, अनुसंधान बोर्डों के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं/एमओयू, प्रदर्शनी, अन्तर स्कूल एवं अन्तर कॉलेज स्तर की प्रतिस्पर्धाओं आदि को भी स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों में रक्षा प्रौद्योगिकियों में रूचि पैदा करने के लिए शुरू की गई है।
- स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों में रक्षा प्रौद्योगिकियों में रूचि पैदा करने के लिए डी आर डी ओके द्वारा बी. टेक/एम. टेक/एमएससी विद्यार्थियों के लिए सवेतन शिक्षता योजना, प्रशिक्षुता, प्रदर्शिनियां, अन्तर कॉलेज स्तर की प्रतिस्पर्धाएं आदि भी शुरू की गई हैं।
- डिफेंस इंडस्ट्री एकेडमिया सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (डीआईएसीओई) : आईआईटी/विश्वविद्यालयों को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को प्रारंभ करने तथा इन डी आर डी ओके द्वारा वित्तपोषित केंद्रों में विशेष परीक्षण सुविधाओं का सृजन करने के लिए डी आर डी ओके आईआईटीओई के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। वर्तमान में, अब तक डी आर डी ओके द्वारा ऐसे 10 डीआईएसीओई स्थापित किए जा चुके हैं।
- साइबर एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पाठ्यक्रम: डी आर डी ओके एआई एवं मशीन लर्निंग (एमएल) में प्रमाणित पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है और अब तक 1000 से अधिक पेशेवरों को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- एमएच आर डी द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के अन्तर्गत प्रायोजित छात्रवृत्तियों के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थान तथा डी आर डी ओके बीच सहयोग: इस योजना के अन्तर्गत, विभिन्न डी आर डी ओके परियोजनाओं में कार्य करने जिससे कि युवा शोध छात्रों को आकर्षित किया जा सके तथा उन्हें डी आर डी ओके की अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों, उच्च स्तर के अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जा सके, के लिए 500 छात्रों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत एआईसीटीई/केन्द्रीय प्रायोजित तकनीकी संस्थानों में पीएचडी पाठ्यक्रम हेतु प्रायोजित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत

त,

छात्रउत्कृष्टप्रौद्योगिकीक्षेत्रमेंजारीआरएण्डडीपरियोजनाकाप्रत्यक्षअनुभवप्राप्तकरनेकाअवसरपातेहैं।

- प्रौद्योगिकीविकासकोष (टीडीएफ) निदेशालय :
टीडीएफकासृजनप्रौद्योगिकीविकासयोजनाकेअन्तर्गतपरियोजनाओंकेलिएकियागयाथा।यहयोजना सार्वजनिक/निजीउद्योगोंविशेषकरएमएसएमईएवंस्टार्टअप्सकीभागीदारीकोप्रोत्साहितकरतीहै, जिससेरक्षाअनुप्रयोगहेतुअत्याधुनिकप्रौद्योगिकीक्षमताबढ़ानेकेलिएवातावरणकानिर्माणहोसके।

पिछलेपांचवर्षोंकेदौरानरक्षाअनुसंधानएवंविकासविभाग (डीडीआरएण्डडी)
द्वाराव्ययकिंगएराशियोंकाविवरणनिम्नलिखितहै:-

(करोड़रु. में)

वर्ष	डीडीआरएण्डडीव्यय
2017-18	15203.04
2018-19	17049.01
2019-20	17375.13
2020-21	15706.98
2021-22	18290.98

रक्षाराज्यमंत्रीश्रीअजयभट्टनेआजलोकसभामेंकुंवरपुष्पेन्द्रसिंहचन्देलद्वारापूछेगएएकप्रश्नकेलिखितउत्तरमेंयहजानकारीलोकसभाकेपटलपररखी।

एबीबी/डीके/डीएस

पत्रसूचनाकार्यालय (रक्षाविंग)
भारतसरकार

‘हरकामदेशकेनाम’

नईदिल्ली:श्रावण14, 1944
शुक्रवार: 05 अगस्त 2022

रक्षाउपकरणोंकीखरीद

पूँजीगतअर्जनहेतुप्रस्तावोंकोदसवर्षीयएकीकृतक्षमताविकासयोजना (आईसीडीपी), पंचवर्षीयरक्षाक्षमताअर्जनयोजना (डीसीएपी) औरदोवर्षीयरोलओवरवार्षिकअर्जनयोजना (एएपी) केसाथप्रारंभकीगईएकविस्तृतप्रक्रियाकेजरिएआगेबढ़ायाजाताहै।योजनाओंकेअनुमोदितहोनेकेबाद 300 करोड़रुपएतककेमामलोंकेलिएसीआईएससीकीअध्यक्षतावालेसेनाअधिप्राप्तिबोर्ड (एसपीबी), 300 करोड़रुपएसेअधिकऔर 500 करोड़रुपएतककेमामलोंकेलिएरक्षासचिवकीअध्यक्षतावालेरक्षाअधिप्राप्तिबोर्ड (डीपीबी) और 500 करोड़रुपएसेअधिककेमामलोंकेलिएरक्षामंत्रीकीअध्यक्षतावालीरक्षाअर्जनपरिषद (डीएसी) द्वाराआवश्यकताहेतुस्वीकृति (एओएन) प्रदानकीजातीहै।आवश्यकताहेतुस्वीकृतिप्रदानकिएजानेकेपश्चात, प्रत्यायोजितवित्तीयशक्तियोंकेअनुसारसेनाओं/रक्षामंत्रालयद्वारानिविदाएंआमंत्रितऔरसंविदाएंप्रदानकीजाती है।वर्ष 2020-21 सेवर्ष 2022-23 (30 जून, 2022 तक) कीअवधिमें 1,83,778.34 करोड़रुपएराशिकी 59 आवश्यकताहेतुस्वीकृतियांप्रदानकीगईहैंऔर 1,19,045.3 करोड़रुपएराशिकी 91 संविदाओंकोअंतिमरूपदियागयाहै।

रक्षाउपस्करकापूँजीगतअर्जनरक्षाअर्जनप्रक्रिया (डीएपी) केप्रावधानोंकेअनुसारकियाजाताहै।डीएपी- 2020 मेंअर्जनक्रियाकलापोकोपूराकरनेकेलिएसमय-सीमानिर्धारितकीगईहै।इसकेअलावा, किग्राकलापोकीनियमितरूपसेनिगरानीकीजातीहैजिससेकिप्रस्तावोंकोअंतिमरूपदियाजानाऔरसंविदाओं काअविलंबनिष्पादनसुनिश्चितकियाजासके।

रक्षाराज्यमंत्रीश्रीअजयभट्टनेआजलोकसभामेंश्रीअशोककुमाररावतद्वारापूछेगएएकप्रश्नकेलिखितउत्तरमेंयहजानकारीलोकसभाकेपटलपररखी।

एबीबी/डीके/डीएस

पत्रसूचनाकार्यालय (रक्षाविंग)

भारतसरकार

‘हरकामदेशकेनाम’

नईदिल्ली:श्रावण14, 1944

शुक्रवार: 05 अगस्त 2022

सशस्त्रसेनाओंकेकार्य-निष्पादनऔरदक्षताकीसंपरीक्षा

इससमितिमेंअध्यक्षकेरूपमेंरक्षासचिवऔरतीनोंसेनाओंकेसहप्रमुख, सचिव (रक्षा) वित्त/ वित्तसलाहकार (डीएस), एकीकृतस्टाफसमितिकेप्रमुख (सीआईएससी), रक्षालेखामहानियंत्रक (सीजीडीए), महानिदेशक (अर्जन) औररक्षामंत्रालयतथारक्षाअनुसंधानएवंविकाससंगठन (डीआरडीओ) केअन्यवरिष्ठअधिकारीसदस्यकेरूपमेंशामिलहैं।निष्पादन/ दक्षतालेखापरीक्षाविश्वसनीय, वास्तविकऔरनिष्पक्षसूचनाउपलब्धकराकर, आयोजना, क्रियान्वयन, विशेषरूपसेपरिणामों/निष्कर्षोंऔरसामान्यरूपसेव्यय/ प्रबंधनकीगुणवत्ताकोप्रभावितकरनेवालेप्रणालियोंमेंकमियोंकोरेखांकितकरकेउच्चस्तरीयप्रबंधनकोबहुमूल्यइ नपुटप्रदानकरनेपरलक्षितहोगी।

सीजीडीएकोनिष्पादनऔरदक्षतालेखापरीक्षाकरनेकाअधिदेश 14 जुलाई, 2022 कोदियागयाथा।लेखापरीक्षाकरनेकेलिएअभिज्ञातविस्तृतक्षेत्रोंमेंरक्षापूँजीगतखरीद, प्रबंधन, संभार-तंत्र, इन्वेंटीस्तर, प्लेटफॉर्मों/परिसंपत्तियोंकाखरखाव, अर्थोर्टीहोल्लिंगसील्डपर्टीकुलर्स (एएचएसपी) इत्यादिकीभूमिकाऔरनिष्पादनशामिलहैं।शीर्षसमितिनिष्पादनऔरदक्षतालेखा-परीक्षाकेलिएकिसीअन्यविशिष्टक्षेत्रकीसिफारिशभीकरसकतीहै।यहसंगठनमेंउत्तरदायित्वऔरपारदर्शिताका अनिवार्यवातावरणबनाकरऔरसततसुधारकेमाध्यमसेकार्यकोप्रभावीढंगसेकरनासुनिश्चितकरकेशासनमेंअर्थ व्यवस्था, प्रभावकारिताऔरदक्षताकोरचनात्मकरूपसेबढ़ावादेगा।

रक्षासैन्यबलोंकेआधुनिकीकरणमेंरक्षाक्षमताओंकाउन्नयनकरनेऔरसंवर्धनकरनेकेलिएनएआधुनिक तमप्लेटफॉर्मों, प्रौद्योगिकियोंऔरशस्त्रप्रणालियोंकाअर्जनशामिलहैऔरयहसुरक्षाचुनौतियोंकेसंपूर्णपरिदृश्यकोअनुकूलबनाने केलिएसशस्त्रबलोंकोतैयारीकीस्थितिमेंखनेकेलिएजोखिमअवधारणा, संक्रियात्मकआवश्यकताओंऔरप्रौद्योगिकीयपरिवर्तनोंपरआधारितएकसततप्रक्रियाहै।सरकारयहसुनिश्चित करनेकोसर्वोच्चप्राथमिकतादेतीहैकिकिसीसंक्रियात्मकआवश्यकताकोपूराकरनेकेलिएसशस्त्रबलपर्याप्तरूप सेसुसज्जितहोंजिसेनएउपस्करोंकोशामिलकरकेतथाक्षमताओंकेप्रौद्योगिकीयउन्नयनसेप्राप्तकियाजासकताहै।

सशस्त्रबलोंकीउपस्करआवश्यकताओंकीयोजनाबनाईजातीहैऔरएकविस्तृतप्रक्रियाद्वाराइसेआगेबढ़ायाजाताहैजिसमेंदसवर्षीयएकीकृतक्षमताविकासयोजना (आईसीडीपी), पंचवर्षीयरक्षाक्षमताअर्जनयोजना (डीसीएपी) औरवार्षिकअर्जनयोजना (एएपी) तथारक्षामंत्रीकीअध्यक्षतावालीरक्षाअर्जनपरिषदद्वाराविचार-विमर्शशामिलहैं।

सरकारदेशमेंसार्वजनिकएवंनिजीक्षेत्रकेउद्योगोंकीक्षमताओंकाउपयोगकरकेरक्षाक्षेत्रमेंस्वदेशीकरण औरआत्मनिर्भरताकेउच्चस्तरोंकोहासिलकरनेकेलिएकईपहलोंपरकार्यकररहीहै।इनउपायोंमेंभारतीयविक्रेताओंमेंअधिप्राप्तिकोप्राथमिकताऔरवरीयतादेनातथालाइसेसिंगव्यवस्थाकाउदारीकरणशामिलहै।

रक्षाअर्जनप्रक्रिया (डीएपी)-2020 रक्षाउपस्करों, प्लेटफॉर्मों, प्रणालियोंऔरउप-प्रणालियोंकेस्वदेशीअभिकल्पन, विकासऔरविनिर्माणकोबढ़ावादेकरभारतसरकारकेआत्मनिर्भरभारतअभियानकेभागकेरूपमेंघोषितरक्षासुधारकार्यकेसिद्धांतोंसेसंचालितहोतीहै।डीएपी 2020 खरीदोभारतीय (अभिकल्पित, विकसितएवंविनिर्मित) (आईडीडीएम) कोसर्वोच्चप्राथमिकतादेताहै।भारतमेंइनहथियारों/प्लेटफॉर्मोंकेउत्पादनकोबढ़ावादेनेकेलिए, आयातपरप्रतिबंधलगानेहेतुहथियारों/प्लेटफॉर्मोंकीसूचियांअधिसूचितकीगईहै।खरीदो (वैश्विक-भारतमेंविनिर्माण) कीएकनईश्रेणीशामिलकीगईहैताकि कलपुर्जोंकाप्रारंभसेहीस्वदेशीकरणकियाजासके।यहश्रेणीविदेशीमूलउपस्करविनिर्माताओं (ओईएमएस) कोभारतमेंउनकीसहायककम्पनीकेमाध्यमसे 'विनिर्माण/अनुरक्षणसंस्थाओं' कीस्थापनाकरनेकेलिएप्रोत्साहितकरतीहै।भारतीयविक्रेताकीपरिभाषाकोभीनईएफडीआईनीतिकेअनुकूलबनायागयाहै।सरकारनेनिजीक्षेत्रसहितभारतीयऔद्योगिकपारि-प्रणालीकीबृहत्तरभागीदारीद्वाराआत्म-निर्भरताकेउद्देश्यकेसाथमेक II औरमेक III श्रेणियोंकोलागूकियाहै।उद्योगद्वारावित्तपोषितविकासपरियोजनाओंकेलिएसरलीकृतमेक-II प्रक्रियाकोअधिसूचितकियागयाहै।एमएसएमईऔरछोटेशिपयार्डोंकेलिए 100 करोड़रुपएसेअधिककेप्रतिवर्षकेआर्डरोंपरआरक्षणप्रदानकिएगएहैं।सरकारनेरक्षाक्षेत्रमेंसामरिकभागीदारीसंबंधीनीतिभीप्रख्यापितकीहैताकिप्रमुखरक्षाप्लेटफार्मऔरउपस्करोंकेविनिर्माणमेंनिजीक्षेत्रकीबृहत्तरभागीदारीकोप्रोत्साहितकियाजासके।

रक्षाराज्यमंत्रीश्रीअजयभट्टनेआजलोकसभामेंश्रीसुधीरगुप्ताएवंअन्यद्वारापूछेगएएकप्रश्नकेलिखितउत्तरमेंयहजानकारीलोकसभाकेपटलपररखी।

एबीबी/डीके/डीएस

पत्रसूचनाकार्यालय (रक्षाविंग)

भारतसरकार

‘हरकामदेशकेनाम’

नईदिल्ली:श्रावण14, 1944

शुक्रवार: 05 अगस्त 2022

रक्षाकेक्षेत्रमेंविज्ञानऔरप्रौद्योगिकीकोअपनाना

सरकारनेरक्षाक्षेत्रमेंविज्ञानऔरप्रौद्योगिकीकेअनुप्रयोगकाउपयोगकरकेअत्याधुनिकरक्षाउत्पादोंकेस्वदेशीविनिर्माणकेलिएकईनीतिगतपहलेंशुरूकीहैं।इनपहलोंमेंअन्यबातोंकेसाथ-साथनिम्नलिखितशामिलहैं:-

- I. रक्षाउपस्करोंकेस्वदेशीडिजाइनऔरविकासकोबढ़ावादेनेहेतु, 'खरीदो { भारतीय-आईडीडीएम (स्वदेशीरूपसेअभिकल्पित, विकसितएवंविनिर्मित) } ' श्रेणीकोपूँजीगतउपस्करोंकीअधिप्राप्तिकेलिएसर्वोच्चप्राथमिकताप्रदानकीगईहै।
- II. अप्रैल 2018 ,
मेंरक्षाउत्कृष्टतानवोन्मेष (आईडीईएक्स) शीर्षकसेरक्षाकेलिएएकनवोन्मेषपारिस्थितिकीतंत्रकीशुरूआतकीगईहै।आईडीईएक्सकाउद्देश्यसूक्ष्म, लघुएवंमध्यमउद्यमों (एमएसएमई) स्टार्टअप ,
वैयक्तिकनवोन्मेषकों ,
अनुसंधानऔरविकाससंस्थानोंऔरशैक्षिकसंस्थानोंसहितउद्योगोंकोशामिलकररक्षाऔरएयरोस्पेसमेंनवोन्मेषऔरप्रौद्योगिकीविकासकोबढ़ावादेनेकेलिएएकपारिस्थितिकीतंत्रकासृजनकरनाऔरउन्हेंऐसेअनुसंधानऔरविकासकार्यकरनेकेलिएअनुदान/वित्तपोषणवअन्यसहायताउपलब्धकरानाहैजिसकीभारतीयरक्षाऔरएयरोस्पेसआवश्यकताओंकेलिएभविष्यमेंअपनानेकीसंभावनाहो।
- III. रक्षामेंआर्टिफिशियलइंटेलिजेन्सअपनानेकेलिएरक्षाएआईपरिषद (डीएआईसी) औररक्षाएआईपरियोजनाएजेंसी (डीएआईपीए) बनाएगएहैं।इसकेअतिरिक्त, एआईरोडमैपकोभीअंतिमरूपदियागयाहै।
- IV. 'खरीदोऔरबनाओ (भारतीय) ' और 'खरीदो (वैश्विक-भारतमेंविनिर्माण) ' श्रेणीकेअंतर्गतडीएपी-2020 मेंविशेषप्रावधानकिंएगएहैंजहांस्वदेशीउत्पादनकोविदेशीओईएमसेप्रौद्योगिकीकेअंतरणकेसाथकिंयाजाताहै।

- V. सरकारी संस्थाओं सहित भारतीय उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी के अंतरण (टीओटी) के माध्यम से विदेशी ओईएम द्वारा ऑफसेट दायित्वों के निस्तारण को भी शामिल किया गया है।
- VI. सरकार ने 'सामरिक साझेदारी' एसपी ('मॉडल अधिसूचित किया है जिसमें एक पारदर्शी और प्रतियोगी प्रक्रिया के जरिए भारतीय कंपनियों के साथ दीर्घकालिक सामरिक भागीदारी स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिनमें वे प्रौद्योगिकी हस्तांतरणों के लिए वैश्विक मूल उपकरण विनिर्माताओं) ओईएम (के साथ गठबंधन करेगा कि घरेलू विनिर्माण अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित की जा सकें।
- VII. रक्षा अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को देश में रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा आरएंडडी बजट के लिए निर्धारित 25% के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शैक्षिक संस्थानों के लिए खोला गया है।
- VIII. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने केन्द्रित अनुसंधान के लिए नौ विशेष क्षेत्रों की पहचान की है, जिनके नाम हैं: प्लेटफार्म, आयुध प्रणाली, सामरिक प्रणालियां, संवेदक और संचार प्रणालियां, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, सामग्री और साधन एवं सैनिक सहायता।
- IX. प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) स्कीम रक्षा और एयरोस्पेस के क्षेत्र में रक्षा प्रौद्योगिकियों के नवोन्मेष, अनुसंधान एवं विकास हेतु उद्योगों विशेषतः स्टार्ट-अप और एमएसएमई के लिए भी 10 करोड़ रु. की धनराशि तक का वित्तपोषण करती है।

इन पहलों के परिणामस्वरूप देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान 155 एमएम आर्टिलरी गन प्रणाली 'धनुष' ; हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस' , सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली 'आकाश' ; मुख्य युद्ध टैंक 'अर्जुन' ; टी-90 टैंक, टी-72 टैंक, सैनिकों को ले जाने वाले कवचित 'बीएमपी-II/IIके', सू-30 एमके1, चीता हेलिकॉप्टर, उन्नत हल्का हेलिकॉप्टर, डोर्नियर डू-228, हार्ड-मोबिलिटी ट्रक, आईएनएस कल्वरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस चैत्रे, पनडुब्बी रोधी युद्ध कावर्ट (एसडब्ल्यूसी), अर्जुन कवचित रिपेयर एंड रिकवरी व्हीकल, ब्रिज लेइंग टैंक, 155 एमएम गोला बारूद के लिए बाई-मॉड्यूलर चार्ज प्रणाली (बीएमसीएस), मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल (एमबीपीवी), वेपन लोकेटिंग रडार (डब्ल्यूएलआर), एकीकृत वायुक्रमान एवं नियंत्रण प्रणाली (आईएसीसीएस), सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (एसडीआर), पायलट रहित लक्ष्य विमान के लिए लक्ष्य पैराशूट, युद्ध टैंकों के लिए ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक साइट, वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, इनशोर पेट्रोल वैसल, ऑफशोर पेट्रोल वैसल, फास्ट इंटरसैटर बोट, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, 25 टीटग आदि सहित कई नवोन्नत उत्पादों का निर्माण किया गया है।

डीआरडीओ द्वारा अभिकल्पित और विकसित मानवरहित हवाई वाहन का पूरी तरह से स्वायत्तरूप में सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। यह उड़ान भावी मानवरहित विमानों के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को सिद्ध करने की ओर एक मील का पत्थर साबित हुई है और एसी सामरिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

रक्षाराज्यमंत्रीश्रीअजयभट्टनेआजलोकसभामेंश्रीरतनलालकटारियाद्वारापूछेगएएकप्रश्नकेलिखितउत्तर
मेंयहजानकारीलोकसभाकेपटलपररखी।

एबीबी/डीके/डीएस

पत्रसूचनाकार्यालय (रक्षाविंग)
भारतसरकार

‘हरकामदेशकेनाम’

नईदिल्ली:श्रावण14, 1944
शुक्रवार: 05 अगस्त 2022

रक्षाउत्पादोंकाउत्पादन

सरकारनेरक्षाउत्पादोंकीस्वदेशीडिजाइन,
विकासऔरविनिर्माणकेलिएईउपायकिएहैं।सैन्यकार्यविभाग (डीएमए/एमओडी) द्वारा 310 मदों
(क्रमशः 101, 108 और 101)
कोशामिलकरतेहुएउनकेसामनेइंगितसमयसीमाओंजिसकेपश्चातइनमदोंकीखरीदस्वदेशीस्रोतोंसेकीजाएगी,
केसाथक्रमशः 21 अगस्त 2020, 31 मई 2021 और 07 अप्रैल 2022
कोतीनसकारात्मकस्वदेशीकरणसूचियांजारीकीगईहैं।उत्पादोंकीडिजाइनऔरविकासकेलिएउद्योगोंकोआगे
आनेकाप्रस्तावदियागयाहै।

इसकेअलावा,
रक्षाविनिर्माणमेंआत्मनिर्भरताकेसततप्रयासऔरडीपीएसयूद्वाराआयातकोन्यूनतमकरनेकेउद्देश्यसेडीडीपी/ए
मओडीनेदिनांक 27 दिसंबर, 2021 और 28 मार्च, 2022 कोउप-प्रणालियों/असेम्बलीज/सब-
असेम्बलीज/घटकोंकीदोसकारात्मकस्वदेशीकरणसूची (पीआईएल) अधिसूचितकीहै।पहलीसूचीमें
2500 मदेंहैंजिनकास्वदेशीकरणपहलेहीकियाजाचुकाहैऔर 351
मदेंहैंजिनकास्वदेशीकरणशुरूकियाजाचुकाहै।दूसरीसूचीमें 107
सामरिकमहत्वकीलाइनरिप्लेसमेंटइकाइयां/मुख्यसब-
असेम्बलीजशामिलहैं।उद्योगोंकेलिएअपनीरुचिदिखानेहेतुइनमदोंकीसूचीऔरउनकाब्यौरासृजनपोर्टलपरउप
लब्धहै।इनमदोंकेलिएएकसमयसीमाअधिसूचितकीगईहैजिसकेपश्चातउनकेआयातपरप्रतिबंधहोगा।अबतक
पहलीसकारात्मकस्वदेशीकरणसूचीकी 351 मदोंमेंसे 154
मदोंऔरदूसरीसकारात्मकस्वदेशीकरणसूचीकी 107 मदोंमेंसे 4
मदोंकास्वदेशीकरणपहलेहीकियाजाचुकाहै।

स्वदेशीसंसाधनोंसेरक्षाउत्पादोंकेस्वदेशीकरणऔरअधिप्राप्तिपरसरकारद्वाराजोरदिएजानेकेकारणपि
छले 4 (चार) वर्षोंअर्थात 2018-19 से 2021-22 मेंविदेशीस्रोतोंसेरक्षाखरीदपरव्यय 46%
सेघटकर 36% होगयाहै।इसकेअलावा, सरकारनेपिछलेचारवर्षोंअर्थात 2018-19 से 2021-22

मेंस्वदेशीस्रोतोंसेपूजीगतखरीदकीविभिन्नश्रेणियोंकेअंतर्गतलगभग 2,51,130 करोड़रु. मूल्यके 162 प्रस्तावोंकोआवश्यकताकीस्वीकृति (एओएन) दीहै।

इसकेअतिरिक्त, आयातोंपररोककेलिएसमयसीमादिसंबर, 2020 सेदिसंबर, 2028 तककेलिएहै, इसलिएइसचरणमेंविदेशीमुद्रासंबंधीबचतोंऔररोजगारकेअवसरोंकाआकलननहींकियाजासकताहै।

रक्षाराज्यमंत्रीश्रीअजयभट्टनेआजलोकसभामेंसुश्रीदेबाश्रीचौधरीद्वारापूछेगएकप्रश्नकेलिखितउत्तरमेंय हजानकारीलोकसभाकेपटलपररखी।

एबीबी/डीके/डीएस